92

कार्यालय आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

पत्रांक /जि0यो०-नलकूप/2011-12 दिनांक जुर

दिनांक जुलाई 04, 2011

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/रा0यो0आ0/जि0 यो0/2008 दिनांक 24.03.2008 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी, चम्पावत के पत्र संख्या मेमो/ 2011—12 दिनांक 31.05.2011 द्वारा प्रेषित संस्तुति के आधार पर जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2011—12 हेतु निम्न योजना की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति उल्लिखित निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

क0 सं0	योजना का नाम	योजना की लागत	जारी प्रशासनिक स्वीकृति	वर्ष 2011.12 में जारी वित्तीय स्वीकृति
1	टनकपुर में 03 संख्या राजकीय नलकूपों के निमार्ण की योजना।	₹ 108.00 लाख	₹ 108.00 लाख	₹ 11.69 लाख (₹ ग्यारह लाख उनसत्तर हजार मात्र)

 जिलाधिकारी चम्पावत सुनिश्चित करेंगे कि योजना में उपरोक्त प्रशासनिक स्वीकृति की धनराशि से अधिक धनराशि किसी भी दशा में बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति किये विना आवंटित नहीं की जायेगी।

2. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें, तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को

सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

3. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आगणनों / पुनरिक्षत आगणनों पर सक्षर स्तर से कार्यों की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4. स्वीकृत धनराशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय, जिसके सम्बन्ध में

तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं है अथवा जो विवादग्रस्त है।

5. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

6. धनराशि केवल उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी जिसके लिए शासन द्वारा धनावंटन किया गया है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

7. उक्त स्वीकृत धनराशि शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों / नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाये तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की

जाय। धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायें।

8. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली

जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

9. योजना निर्माण के संबंध में शासन से समय-समय पर जारी सभी शर्तों एवं नियमों का परिपालन किया जाना अनिवार्य होगा। अवमुक्त धनराशि को शासन द्वारा निदृष्ट मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

्रिप्-(कुणाल शर्मा) आयुक्त।

कार्यालय आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

संख्या ७५२ / जि०यो०—नलकूप/2011—12 तद्दिनांकित। प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

3. सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

4. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड देहरादून।

5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।

6. जिलाधिकारी, चम्पावत ।

7. मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत ।

8. मुख्य अभियन्ता (उत्तर), सिंचाई विभाग हल्द्वानी।

9. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल हल्द्वानी।

10. अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड हल्द्वानी।

11.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन।

12.राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संशाधन सचिवालय देहरादून।

14.अर्थ एवं संख्याधिकारी, चम्पावत ।

15. बरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत ।

16. गार्ड फाईल।

अयुक्त, कुमाऊँ मण्डल।